(d) The plans made by the previous Government did not contemplate removing unemployment within ten years or increasing employment opportunities particularly in the rural areas within a time frame and, therefore, the plans are being changed to make them job-oriented.

मीसा बन्दियों को आर्थिक सहायता देना जिनकी आजीविका का साधन समाप्त हो गया है ।

456. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार उन मीसा बन्दियों को आर्थिक सहायता देने का है जिनकी आजीविका का साधन वर्ष 1975 की आपात स्थिति के दौरान चौपट हो गया था तथा उन मीसा बन्दियों को पुनः नौकरी में लेने का है जिनको उस अवधि के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया था ताकि वे फिर अपना रोजगार आरम्भ कर सकें तथा अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकें ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : उन मीसा बन्दियों को जिनकी आजीविका के साधन आपातस्थिति के दौरान खत्म हो गये थे आर्थिक सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है । किन्तु सरकार ने आन्तरिक आपातस्थिति के दौरान मीसा के अधीन पकड़े गये उन बन्दियों के आश्रितों को जो हिरासत में अथवा हिरासत से छोड़े जाने के तीन महीने के अन्दर मर गये थे, पात्र मामलों में मासिक पेंशन देने की योजना को अन्तिम रूप दिया है ।

10 मई, 1977 को ये अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जो मीसा के अधीन बन्दी बनाये गये थे और जिन्हें अब छोड़ दिया गया है, बहाल कर दिया जाये । अनुदेशों की एक प्रति सभी राज्य सरकारों को भी भेज दी गई है ताकि वे अपने कर्मचारियों के बारे में इसी प्रकार की कार्रवाई करने पर विचार करें ।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

457. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1976 में मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के राजपुर तहसील में पण्या गांव में बिजली लगाने की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की लघु योजना को स्वीकृति दे दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) राजपुर तहसील के ठीकरी ब्लाक की लघु फार्म स्कीमें, जिसमें पण्या गांव सहित 29 गांवों के विद्युतीकरण की परिकल्पना है, ग्राम विद्युतीकरण निगम ने जुलाई, 1976 में अनुमोदित कर दी थीं ।

(ख) स्कीम 1978-79 में पूरी होने का कार्यक्रम है । तथापि राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि पण्या गांव 27 मई, 1977 को विद्युतीकरण कर दिया गया है ।

विशेष केन्द्रीय कारागार, भागलपुर में नक्सलवादियों की हत्या

458. डा० रामजी सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अप्रैल, 1975 में विशेष केन्द्रीय कारागार, भागलपुर में हुई कुछ नक्सलवादियों की निर्मम हत्या की जानकारी है ;

(ख) क्या आपात स्थिति के दौरान इस घटना को रफा-दफा कर दिया गया था ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सामूहिक हत्याकांड की जांच के लिये एक न्यायिक आयोग नियुक्त करने का है : और

(घ) क्या हत्याकांड में मारे गये युवकों के परिवारों को मुआवजा दिया जायेगा ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह): (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ)। प्रश्न नहीं उठता है ।

Alleged access of Shri Sanjay Gandhi to Government Files

459. SHRI KALYAN JAIN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement of former Industries Minister published in the *Hindustan Times* dated 6th May, 1977 that Shri Sanjay Gandhi had free access to Government files and promotions and appointments of officers were decided by him and the honest and sincere officers had often to pay the penalty;

(b) the reaction of Government thereto; and

(c) the action proposed to be taken by Government to check such undue interference in future by persons not connected with Government?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Government consider that it is grossly improper and illegal to permit any unauthorised person to have access to official papers. Government expect that those who are authorised to deal with official business and handle Government papers, will exercise due responsibility in such matters as required by law and established practice.

Grant of Pension to Freedom fighters from Maharashtra

460. SHRI R.K. MHALGI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many applications from Swatantrya Sainiks (Freedom Fighters) of Maharashtra State have been received within last three years in the office of Government of India;

(b) how many of them have been decided;

(c) how many are still pending for decision, District-wise and when they are likely to be decided;

(d) how many of the applicants have been granted pension uptill now; and

(e) what are the grounds on which some of the applications are rejected?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDRURI CHARAN SINGH): (a) During the last three years, i.e, from 1-4-1974 to 31-3-1977, 1818 applications have been received from freedom fighters of Maharashtra State.

(b) All of them have been decided.

(c) None.

(d) From 15-8-72 to 7-6-1977, 10, 310 freedom fighters from Maharashtra have been sanctioned pension.

(e) Applications are rejected on the following grounds:

(i) Failure to furnish adequate documentary evidence in support of the claim of political suffering.